एक्योरेंस दें कि दिल्ली से बांसवाड़ा मैं बात कर सकूं।

ग्रध्यक्ष महोदय : घर से जरूर बात करा धीजिये इनकी ।

## श्वी मूलचन्द डागाः झभी यह अपने घर पर झपनी पत्नी से बात भी नही कर सकते हैं।

SHRI KARTIK ORAON: Sir, the hon. Member has tried to explain in so many terms that the services are very poor and that he is not getting telephone and all that. But, Sir, as per the policy of the Government we have been trying to connect all the district headquarters to the respective State Capitals. At the moment if we want to automatise all the manual exchanges at district headquarters we need 1,15,000 lines automatic exchanges. Our present capacity is about 5,000 equivalent lines of stronger STD and 6,000 lines of automatic equipment. So, we are not in a position to meet the heavy demand on the existing system. It is very difficult. We wish to reach the ideal conditions in our country.

Sir, to far as the hon. Member is concerned he has been pressing hard for telephone connections and even in the Consultative Committee meetings he raised the question of Dungarpur-Banswara-Ratlam radio link. Of course, Banswara-Ratlam route which was supposed to be commissioned by 1984-85 has been advanced and is expected to be completed by 1982-83. As regards Dungarpur-Banswara it cannot be executed earlier and will have to be Commissioned in 1984-35. We could not do this because of limited availability of radio equipment in the first three years of the Plan and pressing demands for equipment from priority routes in North-Eastern region and other important works.

ग्रध्य क्ष महोदय: टेलीफोन का प्रध्न बहुत लम्बा हो गया है श्वी कार्तिक उरांव: ग्रध्यक्ष महोदय, अगर मौका मिले तो मैं माननीय सदस्य को एक भी झर्जीमेंटरी पूछने नहीं दूंगर '

## Crop insurance +

\*187. SHRI CHANDRADEO PRA-SAD VERMA:

## SHRI DAULAT RAM SARAN:

Will the Minister of AGRICUL-TURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that crop insurance has hithertofore been receiving low priority from Government;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have made any study with regard to the crop insurance introduced by certain developed countries particularly by North America and Europe; if so, the details thereof;

(d) whether in view of the importance of agriculture in country's economy, Government propose to give priority to crop insurance in the country; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICUL-TURE AND RURAL RECONSTRUC-TION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House.

## Statement

The Government of India is aware of the importance of Crop Insurance and has been attempting to evolve an appropriate scheme for implementation in the country. Even though' the Expert Committee appointed by the Government of India in 1970 held that it would not be advisable to introduce crop insurance in the near

5

future since it would involve diversion of scarce financial and administrative resources on a significant scale from the more promising measures which raise agricultural productivity and at the same time reduce yield variability, the Government of India did not accept the conclusion. The Government decided to entrust the General Insurance Corporation of India with the responsibility of implementing pilot schemes. During the period 1973 to 1979, the General Insurance Corporation of India implemented pilot schemes based on an individual approach in selected areas in the States of Andhra Pradesh, Guja-Karnataka, Madhya Pradesh, rat. Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal. Cotton, wheat, groundnut and paddy were the crops covered by crop insurance. All these schemes proved to be unviaable and unsuitable for adoption on a countrywide basis due to several administrative and financial constraints. An alternative method of implementing crop insurance by adopting area apapproach was therefore proposed and discussed with the State Govern-A Pilot Crop ments. Insurance Scheme based on area approach has been drawn up by the General Insurance Corporation of India and is being currently implemented in the four States of Gujarat, Maharashira, Tamil Nadu and West Bengal. In the Sixth Plan 1980-85, the Government propose to extend the coverage of this Pilot Crop Insurance scheme.

2. The Government have not made any detailed studies of the Crop Insurance Scheme in North America and Europe. The experience of another developed country, i.e., Japan, has been studied. This shows that crop insurance scheme would require a strong administrative net-work for implementation and that the scheme will have to be supported by the Government with substantial subsidy. The crop insurance schemes of developed countries may not be quite appropriate in the context of a developing country like India. Crop insurance scheme for India has to be developed with reference to the conditions obtaining in this country.

श्वी चन्द्र देव प्रसाद वर्मा: मध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1970 में एक विशेषक समिति फसल बीमा के लिए नियुनत की थी, उसने अपनी रिपोर्ट नहीं में टी, लेकिन रुसके बावजूद सरकार ने यह पास किया कि फसल बीमा चलानी है और इसके निर्णय के अनुसार 4 राज्यों में सामान्य बीमा निगम के प्रधीन यह कार्य मौपा गया, जिनके नाम हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु श्रीर पण्चिम रुंगाल ।

ग्रध्यक्ष महोदय , बाढ, ग्रोले, सूखा से उत्तर भारत यानी बिहार ग्रौर उत्तर भारत यानी बिहार ग्रौर उत्तर प्रदेश तथा बंगाल ग्रादि कई राज्य हर वर्ष वर्षाद हो जाते हैं ग्रौर किसानों की ग्रपार क्षति होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन से राज्य हैं, जिनके साथ सरकार ग्रभी विचार-विमर्श कर रही द्वै ।

छुषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण ग्रीर सिंचाई मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह ) : चार स्टेट्स ग्रीर हैं, जिनमें ग्रभी जनरल इनशोरेंस कार्पोरेशन के साथ इस बात पर विचार हो रहा है कि काथ इनशोरेंस लागू की जाये। वे राज्य हैं : यू० पी०, राजस्थान, हरियाणा ग्रीर कर्नाटक ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : इस विवरण में कहा गया है कि सरकार ने यूरोप प्रौर अमरीका की फसल कीमा योजना का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है ग्रीर इस बारे में सिर्फ जापान के अनुभव का अध्ययन किया है । इसमें यह भी कहा गया है कि विकसित देशों के अध्ययन से कोई जाम नहीं है । मैं यह जानना भाहता हूं कि सरकार ने उन देशों के अनुभव का अध्ययन कर के फिर अविकसित या विकासशील देश के लिए ऐसी कोई योजना लागू करने का उपाय क्यों नहीं किया । उिसने बैठे बैठे यह तय कर लिया कि जैसी बोजना विकसित देशों में है, बैसी यहां पर लागू नहीं हो सकती है । क्या सरकाप ने कोई नई योजना बनाई है, जिसे उसके स्थान पर यहां खागू किया जा सके ?

RAO BIRENDRA SINGH: The thinking about crop insurance has been going on ever since the country achieved Independence. There have been various committees appointed from time to time and it was always found that a developing country like India with scanty resources could not afford crop insurance scheme which entails very heavy amount by way of subsidy. In developed countries the situation is absolutely different. For instance, in Japan crop insurance is compulsory for certain categories of farmers but there the scheme is operated through various relief associations of the farmers themselves. In India the crop insurance scheme has been taken up on an experimental basis in certain pilot projects.

श्वी दौलत राम सारण: ग्रन्थक्ष महोदय, क्या सरकार किसानों के हित में नीति के तौर पर फ़सल बीमा योजना लाग् करना आवश्यक समझती है, यदि हां, तो फिर इस सम्बन्ध में इतने विलम्ब का क्या कारण है ? सरकार ने जो पायलट प्रोजेक्ट लागू करने की बात कही है, उसमें तीन चार फसलें ली हैं, ग्रीर वह योजना भी ठीक तरह से लागू नहीं की गई है ! मंबी महोत्य ने कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों की बात कही है । मैं यह जानना चाहता हं कि वे प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं, मंबी महोदय उसका विवरण देने का कप्ट करें, ताकि हम भी समझ सकें।

राव वीरेन्द्र सिंह : प्रशासनिक कठिनाइयों के साथ सब् से बड़ी कठिनाई धनराणि की है : जहां कहीं भी भ्रमी तक यह तज्बी किया गया है, उसकी बिना पर अगर में ब्यौरा दं, तो माननीय सदस्य समझ जग्योंगे कि इसके लिए बहत पैसे की उत्ररूरत है। 1978-79 में एक्स-पेरिमेंटल स्कीम 3800 हैक्टेयर के लिए थी । उसमें प्रीमियम वसूल हम्रा 3.38.000 रुपये ग्रीर उस पर क्लेम किया गया 36,06,000 रुपये, ग्ररा यानी जितना प्रीमियम इकटठा हुआ, उससे बारह गुना क्लेम का देना पड़ा जेनरल इनकोरेंस कार्पोरेशन को । इसी तरीके से पहले भी कहीं कहीं जो तज्बी किया गया था, उसमें भी हैवी लास हग्रा । 1188 हैक्टयर में यह 73 से 76 तक कुछ इलाकों में लागुकी गई थी ग्रौर उस में भीमिथम 1 लाख 16 हजार इकट्ठा हन्रा था जब कि ऱलेम तय किया गया 1 लाख 82 हजार का । यह स्कीम अभी सिफे उन इलाकों में लागू की जा रही है जहां कूदरत की तरफ से नुकसान कम होने की सभावना होती है, जो लो रिस्क एरियाज हैं। ग्रब हमारी कोशिश हो यह है कि इस के ग्रलावा इस को भी मीडियम रिस्क एरियाज के ग्रन्दर भी ट्राई किया जाय । उस की योजनाहै ।

यह अभी तक जो काप इन्ण्योरेंस स्कीम हमारे देश में चल रही है वह फसल का बीमा नहीं है, बल्कि वह जो बैंकों से किसानों को कर्जमिलता है उस कर्जे की रकमं का बीमा है ताकि ग्रगर नुकसान कुछ ज्यादा हो जाय तो उसके हिसाब से जो रकम बैंक को ग्रदा करनी है वह किसान से वसूल न की जाय बल्कि जनरल इन्झ्योरेंस कम्पनी और स्टेट गवर्नमेंट जिस का भी कुछ हिस्सा होता है उन की तरफ से वह बैंक को ग्रदा कर दी जाय जिससे कि किसान के ऊपर बोझ न पडे। ग्रभी यह उसी हद् तक है। ग्रगले साल के ग्रन्दर इस को बढाने की योजना है।

पिछले साल भी इस को काफ़ी हद् तक बढ़ाया गया है। कुछ स्टेट्स श्रौर इस के ऊपर विचार कर रही हैं कि इसको लागू करें। दूसरी स्टेट्स भी इसमें कुछ इनीसिएटिव लेंगी तो उनको भी इस में लिया जा सकेगा।

SHRI NIREN GHOSH: The hon, Minister said that it is not real crop insurance but rather some variant of it. That is why perhaps more money has got to be spent. The poor farmers and the marginal farmers have not got any benefit out of your price fixation. They have not got any benefit from independence till today. The FCI says that they are not under any obligation to buy from them at fixed price. The price fixation of APC does not help them. In view of this, it will be of benefit to the farmers if you introduce at least Crop Insurance Scheme. Why should not the Government think of introducing Crop Insurance Scheme at least in respect of the poor and marginal farmers immediately? Sir, much time has gone by.

RAO BIRENDRA SINGH: The question of crop insurance is not related to the question of minimum support price. That is different altogether. You cannot combine these two.

SHRI NIREN GHOSH: Poor farmers and marginal farmers do not get any benefit. If the Crop Insurance Scheme is introduced they will get benefit even under the Price Support Scheme.

MR. SPEAKER: This is only when there is some damage or some calamity is caused.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: May I know whether it is not possible to introduce Crop Insurance Scheme where the Banks have adopted some of these villages? Agricultural operations have been done under the supervision of Agricultural University Officials. In these cases the risk would be very much less. So, I would like to know whether Government is thinking of introducing Crop Insurance Scheme in such villages.

RAO BIRENDRA SINGH: I have already stated that some action has been taken by way of pilot projects. 4 States have adopted it already. 4 more States are thinking of adopting it.

श्री गिरधारी लाल व्यास : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हं, दो प्रकार से किसान को नुकसान होता है----एक तो प्राक्वतिक प्रकोप से भौर दूसरे सरकार की कमियों की वजह से, प्राक्वतिक प्रकोप से तो जैसे फैमिन है, ग्रोले पड़ जाते हैं या कीटाणु लग जाते हैं, इस तरह से नुकसान होता है । सरकार की गफलत से जो नुकसान होता है उस में बिजली न मिलना, वानी न मिलना या जो ग्रन्थ प्रकार के साधन काप को जीवित रखने के लिए उपलब्ध होने चाहिए वह उपलब्ध नहीं होते, उन से उस को नुकसान हो जाता है। तो इन में से किस के ठपर सरकार थह काप इन्क्योरेंस की कार्यवाही चलाना चाहती है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : काप इंग्यो स तो जिस ढंग से इस वक्त कवर हो रही है वह तो मैंने ग्रर्ज कर दिया । सरकार को भी दिक्कर्ते होती हैं। उस की वजह से जो किसान को हानि पहुंचती है उस का किस तरीके से हम इन्क्योरेंस कर सकते हैं उस के लिए माननीय सदस्य ग्रगर हमारे पास कोई सजवान भेजेंगे तो हम अस पर विचार कर सकते हैं।

भी गिरमारी लाल व्यास : नह तो घाप बुद सोप सकते हैं। (व्यवनाल) ....